1	2	3
3.	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	1. नांगल 2. भटिंडा 3. पानीपत 4. विजयपुर
4.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०	1. उद्योगमंडल 2. कोचीन
5.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	1. ट्राम्बे 2. थाल
6.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1. मद्रास
7.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	1. पारादीप
8.	पाइराइटस फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	1. अमझोर
9.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	1. नेवेली
10.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया	1. राउरकेला 2. भिलाई 3 दुर्गापुर 4. बोकारो
11.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड*	1. खेती

*ये एक्क अधिकतर उप-उत्पाद के रूप में केवल उर्वरकों का उत्पादन करते हैं।

जिला उद्योग केन्द्र

634. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में देश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में ऐसे उद्योग केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है और सरकार किस तरह इस निर्णय को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) क्या इन स्थापित नये उद्योग केन्द्रों द्वारा नये उद्यमियों को जमीन, ऋण औद्योगिक लाइसेंस और उद्योग से संबंधित दिशा निर्देश तथा आधुनिकतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों का मुख्य कार्य क्या होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार ने देश में अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश में गिरावट

635. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किये जा रहे

पूंजी निवेश की राशि में लगातार गिरावट आती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकारी पूंजी निवेश की कमी के कारण इन उपक्रमों द्वारा निरन्तर ऋण लिये जाने से इन उपक्रमों की ऋण राशि में भारी वृद्धि हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इन उपक्रमों द्वारा वर्ष 1986-87 में कुल कितनी राशि ऋण के रूप में ली गयी थी; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान यह राशि कितनी थी और इस तरह के ऋणों पर कितना वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगाई जा रही पूंजी (सामान्य शेयर पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋणों) में निरंतर कोई कमी नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों में क्रमशः 2088.06 करोड़ रुपये तथा 8759.17 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है । वर्ष 1989-90 के दौरान नकद उधार तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऐसे ऋणों पर कुल देय ब्याज की राशि 5341.10 करोड़ रु० थी ।

No industry district in Uttar Pradesh

636. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the criteria for declaring a district as 'No Industry District';

(b) the details of no industry districts in Uttar Pradesh; and

(c) what are the reasons for not opening new industries in industrially backward districts of Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) 'No Industry Districts' are those which did not have any large or medium scale industry as per the District Industries Centres Action Plan, 1979-80.

(b) In Uttar Pradesh, Banda, Chamoli, Fatehpur, Hamirpur, Jalaun, Jaunpur, Pauri Garhwal, Sultanpur, Tehri Garhwal, Uttar Kashi, and Kanpur Dehat have been declared as 'No Industry Districts'.

(c) During the period 1989—91 (upto June), 222 letters of Intent and 63 Industrial Licences have been issued to the dustrial Licences have been issued to the dition, under the new growth centre scheme, Shivraipur Padampur in Pauri Garhwal district has been selected as one of the growth centres.

.. Rules relating to leave encashment

637. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the rules relating to leave encashment for Central Government employees;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when the final decision is likely to be taken in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) The Board of Arbitration set up under the Scheme for Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration for Central Government Employees (JCM Scheme) has given two Awards (i) Encashment of Half Pay Leave on superannuation and (ii) Encashment of earned leave while in service to Central Government employees from 14-7-82 and 1-4-89 respectively subject to certain conditions;